बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 178 ● नई दिल्ली ● वीरवार 30 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कर रहे थे सुनवाई, स्क्रीन पर अचानक चल पड़ा अश्लील वीडियो; बंद करनी पड़ी वीडी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बुधवार दिन में एक ऐसी घटना घटी पूरी कार्यवाही बाधित हो गई। इसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक नहीं दो बार बंद करना पड़ गया और यह अब भी बंद ही है। गौरतलब है कि बुधवार दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जारी थी। इसी बीच अचानक किसी रैंडम यूजर ने वीसो में लॉगइन किया और अश्लील वीडियो और संगीत चलाने लगा। स्क्रीन पर जैसे ही यह वीडियो प्रसारित हुआ पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया और वीसो को तुरंत बंद कराया गया।

सुधार के नाम पर धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली ।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि उत्तर भारत में रहने वाला कोई गैर-आस्थावान व्यक्ति आखिर किस आधार पर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांग सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म की मूल संरचना को कमजोर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत की सभ्यता और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 भी इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से विकसित हुए हैं। अदालत के मुताबिक, वर्तमान को समझने के लिए अतीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नौ जजों की संविधान पीठ ने कहा कि मंदिर प्रवेश के अधिकार से जुड़े मामलों में यह देखना जरूरी है कि दावा करने वाला व्यक्ति भक्त है या नहीं। अदालत ने संकेत दिया कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में आस्था का पहलू भी अहम भूमिका निभाता है। यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई, जिनमें सबरीमाला समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। अदालत इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संतुलन पर विचार कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व फैसला अब भी प्रभावी है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसके बावजूद महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिसका कारण राज्य सरकार का पर्याप्त सहयोग न होना बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत धर्म की परिभाषा तय नहीं करती, बल्कि यह तय करना धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का विषय है। सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा हुई कि क्या संविधान को पूरी तरह नए दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए या फिर ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस पर दोनों पक्षों के बीच गहन बहस हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच मंदिर में प्रवेश से रोकना उनके जीवन के महत्वपूर्ण दौर में अधिकारों से वंचित करना है। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस निर्णय में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को असंवैधानिक करार दिया गया था। बावजूद इसके, आज भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने इस पर स्पष्ट किया कि महिला को उसके सामाजिक वर्ग के कारण नहीं, बल्कि आयु समूह के आधार पर रोका गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विविधता ही भारत की ताकत है और संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि किसी धार्मिक प्रथा को आवश्यक या गैर-आवश्यक घोषित करना न्यायालय के लिए बेहद जटिल कार्य है।

दिनदहाड़े 70 लाख की लूट का चौंकाने वाला खुलासा, दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा

नई दिल्ली । दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में दिनदहाड़े हुई 70 लाख रुपये की बड़ी लूट की वारदात को पुलिस ने कुछ ही दिनों में सुलझा लिया है. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 53 लाख 40 हजार रुपये की रकम बरामद की गई है. वहीं इस पूरे मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, यह घटना 31 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे की है. शिकायतकर्ता के दो कर्मचारी 70 लाख रुपये नकद लेकर जा रहे थे, तभी कृषि कुंज के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोककर लूट लिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस लूट में अंदर की जानकारी का इस्तेमाल किया गया था. कर्मचारी विकास ने अपने साथियों मोहम्मद कैफ, ऋषि यादव और सौरभ उर्फ बचा के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. इसी जानकारी के आधार पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की पहचान की. इसके बाद मुखबिरों की मदद और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से सभी आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. लगातार दबिश के बाद चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया.पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 लाख से यादा की नकदी और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है. कुछ आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है.

किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है दिल्ली सरकार- रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने से बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल से रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी गई है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी। उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत अब गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है ताकि मौसम से प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके, हालांकि गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट के तहत खरीदा गया गेहूं अलग तरीके से संभाला जाएगा। इस गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखकर उसका अलग भंडारण किया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब अलग से रखा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे देर तक स्टोर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली के भीतर ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भंडारण के दौरान इस गेहूं की गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय किसानों को राहत देने, उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जिम्मेदार और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

एनजीटी को डीडीए ने दी जानकारी- यमुना किनारे ओ-जोन में 90 अवैध कॉलोनियां, 15.38 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई

नई दिल्ली । यमुना नदी के किनारे बने ओ-जोन (फ्लड प्लेन) में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी अपनी रिपोर्ट डीडीए ने बताया कि यमुना के ओ-जोन के करीब 9700 हेक्टेयर क्षेत्र में 90 अवैध कॉलोनियां बसी हैं। ये कॉलोनियां लगभग 807 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। इस पूरे इलाके में डीडीए की करीब 3969.54 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से 184.2 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा था। अब तक 15.38 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया जा चुका है जबकि बाकी हिस्सों में कार्रवाई जारी है। डीडीए ने रिपोर्ट में बताया कि इन अवैध कॉलोनियों से निकलने वाला गंदा पानी और सीवर सीधे यमुना नदी में गिर रहा है। इससे नदी का पानी तेजी से प्रदूषित हो रहा है जो पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। यही वजह है कि इन कॉलोनियों को हटाना जरूरी है।

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये कॉलोनियां एक दिन में नहीं बनी हैं, बल्कि लंबे समय तक हुई लापरवाही का नतीजा हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन अवैध बस्तियों को पूरी तरह हटाया जाए ताकि यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके और फ्लड प्लेन क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके।

पूरे इलाके का दोबारा ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई डीडीए के वाइस चेयरमैन करेंगे। डीडीए को दोबारा ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नई अवैध कॉलोनियों की पहचान की जा सके। अदालत ने कहा है कि जहां-जहां नई कॉलोनियां बन रही हैं वहां सार्वजनिक नोटिस लगाए जाएं ताकि लोग शिकायत कर सकें। इस अभियान में दिल्ली पुलिस को भी सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ओ-जोन क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, ओ-जोन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। साथ ही, इस मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से मार्गदर्शन मांगा गया है।

प्राधिकरण का कहना है कि यमुना के फ्लड प्लेन को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। यहां नेचर पार्क, बांस पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क और रिवरफ्रंट जैसे कई पर्यावरणीय प्रोजेक्ट भी विकसित किए जा रहे हैं।

दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल हो रहा पूरा, नए अध्यक्ष के लिए रेस में ये नाम आगे

नई दिल्ली । दिल्ली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पार्टी के भीतर नए अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. संगठन के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कुछ नए नाम तेजी से उभरकर सामने आए हैं, जबकि एक वर्ग मौजूदा नेतृत्व को ही जारी रखने के पक्ष में नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो नई दिल्ली नगर परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और राजीव बब्बर को अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है. तीनों नेताओं की संगठन में पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी को उनकी ताकत के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी सफलता के चलते वीरेंद्र सचदेवा को ही दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. उनके नेतृत्व में पार्टी ने लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की, जो उनके पक्ष में मजबूत तर्क बनता है. वीरेंद्र सचदेवा ने मार्च में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं. पार्टी के संविधान के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और कोई भी नेता लगातार दो कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है. ऐसे में उनके लिए दूसरा कार्यकाल पूरी तरह संभव माना जा रहा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा. संभावना जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है. वीरेंद्र सचदेवा को दिसंबर 2022 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और मार्च 2023 में उन्होंने पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभाली. उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की. इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी ने दिल्ली की सभी सात सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा.

सामाजिक समीकरण भी अहम

बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों में इस बार सामाजिक संतुलन भी अहम भूमिका निभा सकता है. कुलजीत सिंह चहल जाट समुदाय से आते हैं, जबकि वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा और राजीव बब्बर पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं जय प्रकाश का नाम गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में चर्चा में है. कुलजीत सिंह चहल को NaMo ऐप के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के करीब माना जाता है. वहीं, हर्ष मल्होत्रा की पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी नेता के रूप में है. ऐसे में संगठनात्मक पकड़ और वैचारिक जुड़ाव दोनों ही चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

राजीव बब्बर का लंबा संगठनात्मक अनुभव, चुनावी रणनीति में अहम भूमिका

राजीव बब्बर भी इस दौड़ में एक मजबूत नाम के तौर पर उभर रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक और एलएलबी करने वाले बब्बर छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी संगठन तक लंबा अनुभव रखते हैं. 2006 में युवा मोर्चा से जुड़ने के बाद बब्बर ने तेजी से संगठन में अपनी पहचान बनाई. वे प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे और कई राज्यों के प्रभारी भी बने.

ऐतिहासिक वोटिंग लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत

पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। लोकतंत्र में लोक की भारी भरकम भागीदारी लोकतंत्र के लिए शुभ और सकारात्मक संकेत है। दोनों राज्यों में क्रमशः 92.72 फीसदी और 85.14 फीसदी मतदान के साथ नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान को देश के मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेत बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब विशेष मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। आजकल 60-70 फीसदी मतदान हो जाए तो राजनीतिक दल और नेतागण राहत की सांस लेते हैं। बंगाल के इस बार के मतदान पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुलासा किया है कि आजादी के बाद देश में सबसे अधिक मतदान बंगाल में हुआ है, तो 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में इतना अधिक मतदान किया गया है। ये बंपर वोटिंग कहती क्या है? क्या संकेत दे रही है? क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया में ये नया बदलाव है? कभी 50-55 प्रतिशत वोटिंग में सरकारें बन जाया करती थीं और आज पश्चिम बंगाल में 92 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। आखिर वजह क्या है? क्या लोग वोट के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं या वजह कुछ और है? पश्चिम बंगाल में 2001 विधानसभा चुनाव में 75.3 प्रतिशत मतदान हुआ था। 2001 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 199 सीटों वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी। ये उसकी लगातार छठी बार जीत थी। लेफ्ट फ्रंट में सीपीआई–एम 143 सीटें, फॉरवर्ड ब्लॉक को 25 सीटें, आरएसपी को 17 सीटें, सीपीआई को 7 सीटें और बाकी सहयोगियों को 7 सीटें मिली थीं। वहीं विपक्ष को कुल 86 सीटें मिलीं। तृणमूल कांग्रेस को 60 सीटें, कांग्रेस को 26 सीटें, जीएनएलएफ को 3 सीटें और अन्य/निर्दलीय को 6 सीटें मिलीं थीं। तब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने ज्योति बसु के बाद कमान संभाली थी। फिर 2011 में 84.3 फीसदी हुआ। 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन का अंत था। सरकार यूपीए की बनी थी और उसने कुल 226 सीटें जीती थीं। तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें, कांग्रेस को 42 सीटें मिलीं। वहीं विपक्ष में लेफ्ट फ्रंट को 62 सीटें मिली थीं। सीपीआई–एम को 40 सीटें, फॉरवर्ड ब्लॉक को 11 सीटें, आएसपी को 7 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें, एसपी को 1 सीट, डीएसपी को 1 सीट मिली। वहीं अन्य में जीजेएम को 3 सीटें, निर्दलीय और अन्य को 2 सीटें मिलीं। ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनीं। लेफ्ट फ्रंट को 136 सीटों का नुक्सान हुआ था। 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनीं।

तृणमूल कांग्रेस को कुल 211 सीटें आईं और 44.91 फीसदी वोट शेयर रहा। विपक्ष को कुल 77 सीटें मिलीं। कांग्रेस को 44 सीटें, सीपीआई–एम को 26 सीटें, क्क्क को 3 सीटें, जीजेएम को 3 सीटें, अन्य लेफ्ट फ्रंट सहयोगी को 4 सीटें मिलीं। कुल मतदान 83.02 फीसदी हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने मिलकर ÷महाजोत÷ गठबंधन बनाया था, जिसे कुल 74 सीटें मिलीं। 2021 में 81.6 फीसदी मतदान हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनीं। टीएमसी को कुल 215 सीटें मिलीं और 48.02 फीसदी वोट शेयर मिला। विपक्ष को कुल 78 सीटें मिलीं। बीजेपी को 77 सीटें और राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी को 1 सीट मिली। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को एक भी सीट नहीं मिली। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं लेकिन बाद में भवानीपुर उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहीं। तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 2001 विधानसभा में 59.1 फीसदी मतदान हुआ। 2011 में 78.0 फीसदी मतदान हुआ। 2021 में 72.7 फीसदी मतदान हुआ। 2001 में एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री जे. जयललिता और फिर ओ. पन्नीरसेल्वम बने। एआईएडीएमके गठबंधन को 196 सीटें मिलीं। अकेले एआईएडीएमके को 132 सीटें मिलीं। फिर 2011 चुनाव में भी एआईएडीएमके की सरकार बनी। मुख्यमंत्री जे. जयललिता बनीं। एआईएडीएमके गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। 2016 में भी एआईएडीएमके 136 सीटों के साथ सत्ता में लौटी थी। 2021 में डीएमके गठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन. डीएमके गठबंधन को 159 सीटें मिलीं। अकेले डीएमके को 133 सीटें मिलीं। एआईएडीएमके का 10 साल का शासन खत्म हुआ। अब 2026 में 85.1 फीसदी मतदान हुआ है। ये आंकड़े भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि ज्यादा मतदान का मतलब सरकार बदल रही है। हां, चांसेज इसी के ज्यादा होते हैं। बात 2026 की जाए तो इस बार अतीत के तमाम कीर्तिमान बौने हो गए हैं और लोकतंत्र की निर्णायक भागीदारी ने नए मील-पत्थर गाड़ दिए हैं। ये मतदान इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बंगाल में कुल 91 लाख से अधिक और तमिलनाडु में 57 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम, एसआईआर के जरिए, काट दिए गए थे। अब भी लाखों के मताधिकार अधर में लटके हैं। एसआईआर का खौफ और भय था, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही थीं कि यदि वोट नहीं देंगे तो अंतत नागरिकता भी जा सकती है! यहां हम स्पष्ट बता दें कि न तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है और न ही देश का कानून है कि वोट न देने से नागरिकता रद्द की जा सकती है। आप बहकावे में न आएं, भ्रमित न हों और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी भारतीयता कोई खैरात नहीं है। वह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बहरहाल बंपर मतदान की व्याख्याएं शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 'एग्जिट पोल' दावा कर रहा है कि भाजपा प्रथम चरण की 152 सीटों में से 100 सीटें पार कर चुकी है। हालांकि भाजपा ने 125 सीटों पर प्रचंड जीत का दावा किया है। ये आंकड़े सरकार बनने या बदलने से ज्यादा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत के चुनावी प्रक्रिया में समय के साथ तेजी के साथ सुधार हो रहा है।

सम्पादकीय...

शिक्षा और उद्योग का संगम: अलीगढ़ के औद्योगिक पुनर्जागरण और आत्मनिर्भरता की नई इबारत

अलीगढ़ जनपद की पहचान सदैव से उसके ऐतिहासिक गौरव, उच्च शैक्षणिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध तालों से रही है, लेकिन अब यह जनपद अपनी पारंपरिक पहचान को आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ जोड़कर एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान पहल, जो स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप देने की दिशा में अग्रसर है, न केवल एक प्रशासनिक सुधार है बल्कि यह 'स्किल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे राष्ट्रीय संकल्पों को धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम भी है। मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार प्रो. डीपी सिंह के हालिया अलीगढ़ दौरे ने इस विजन को और स्पष्ट कर दिया है कि अब समय पारंपरिक किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर कौशल आधारित व्यावहारिक शिक्षा को अपनाने का है। यह पहल 'एक जनपद, एक उत्पाद' (क्क्च) योजना को सीधे शिक्षा तंत्र से जोड़ती है, जिससे स्थानीय युवाओं को अपनी ही माटी में रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। अलीगढ़ के संदर्भ में इसका औचित्य और भी गहरा हो जाता है क्योंकि यहाँ का ताला और हार्डवेयर उद्योग केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है। यदि तकनीकी संस्थानों में ताला निर्माण, आधुनिक मशीनिंग और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है, तो इससे शिक्षा और उद्योग के बीच की वह दूरी समाप्त हो जाएगी जो अक्सर स्नातक होने के बाद भी युवाओं को बेरोजगार बनाए रखती है। वर्तमान समसामयिक परिदृश्य में जब जेवर एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल रहे हैं, तब कुशल जनशक्ति (ापससमक डंदचवूमत) की मांग भी तेजी से बढ़ी है। सीमेंट उद्योग और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए नए ट्रेड और कौशल आधारित पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय प्रतिभाओं को बाहरी दुनिया में भटकने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही सम्मानजनक आजीविका मिले। यह रणनीतिक बदलाव छात्रों को न केवल नौकरी पाने के काबिल बनाएगा, बल्कि उनमें उद्यमिता का बीज भी बोएगा, जिससे वे छोटे-छोटे स्टार्टअप और कार्यशालाओं के माध्यम से स्वयं 'रोजगार दाता' बन सकेंगे। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि समय-समय पर पाठ्यक्रमों को बाजार की मांग के अनुसार अपडेट किया जा सके। जेडी माध्यमिक मनोज गिरी जैसे अधिकारियों का इस पहल को समर्थन देना इस बात की पुष्टि करता है कि शासन और प्रशासन दोनों ही शिक्षा को विकास और समृद्धि का आधार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो अलीगढ़ की यह 'इंडस्ट्री-कनेक्ट' शिक्षा प्रणाली पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

सन टेन के लिए घरेलू उपाय

शहनाज़ हुसैन

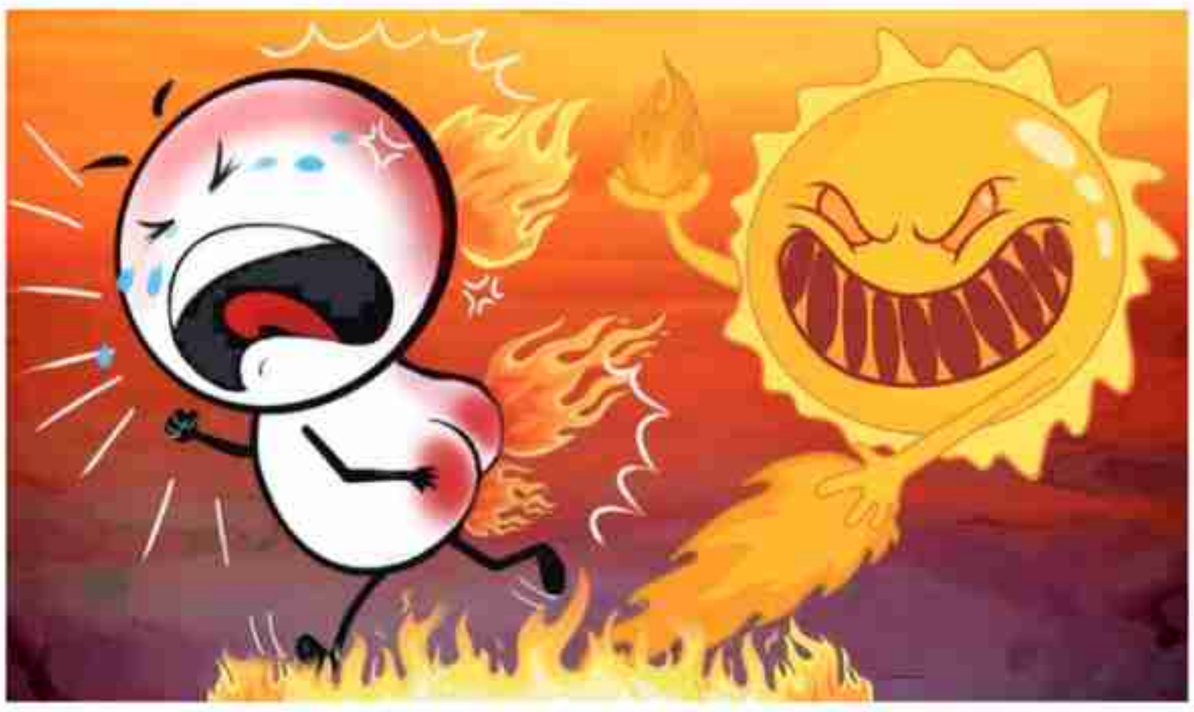

गर्मियों का मौसम हो और चेहरे पर धूप का असर ना दिखे ऐसा कम ही होता है/ , गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग टैनिंग को लेकर परेशान रहते हैं / हालाँकि कुछ लोग चेहरे पर कपड़ा बांध कर निकलते हैं लेकिन कड़कती धूप से बचने के लाख जतन करके भी इससे पूरी तरह बचना मुश्किल हो जाता है/ गर्मियों में घर से बाहर निकलने पर या गर्मियों की छुट्टिओं में समुद्र तट घूमते हैं तो आपकी त्वचा सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों के सम्पर्क में आने, प्रदूषण और गन्दगी के सम्पर्क में आने से सांवली पड़ जाती है / चेहरे पर सन टेन की बजह से चेहरे का सही रंग चला जाता है और चेहरे का आकर्षण भी खतम हो जाता है जिससे चेहरा डल दिखाई देने लगता है / इस मौसम में सन टेन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कई बार लोग बड़ी कम्पनियों के महँगे उत्पादों का उपयोग करते हैं लेकिन यह उत्पाद कई बार त्वचा के अनुकूल नहीं होते जिसकी बजह से त्वचा की अनेक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं / ऐसे में धुप से बचने के लिए आप कुछ होम मेड फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं जोकि आपकी त्वचा को मुलायम और कोमल बनाये रखेंगे /

1 --पपीता फेस पैक

यदि आपका चेहरा धूप में अधिक समय तक रहने से काला पड़ गया है तो पपीते का फेस पैक काफी मददगार साबित हो सकता है / इसके लिए आप पका हुआ पपीता और निम्बू ले लें / पपीते का छिलका उतार कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैश कर लें और इसमें निम्बू की कुछ बुँदे मिला लें /इस मिश्रण को चेहरे पर लगा कर प्रकृतिक तरीके से सूखने के बाद ताजे पानी से चेहरा धो डालें / इसे आप रोजाना नियमित रूप से लगा सकतीं हैं / सन टेन हटाने के लिए शहद और पपीते का फेस पैक भी काफी सहायक होता है / आप थोड़ा सा पपीता मैश करके इसमें कुछ बुँदे शहद की मिलाकर फेस पैक तैयार कर लें / इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगा कर सूखने दें और बाद में साफ ताजे पानी से धो डलें / यह पैक सन टेन को हटाने के साथ ही त्वचा को पौषण भी देता है जिससे आपकी त्वचा कोमल बन जाती है /

2 --नींबू का फेस पैक ---

नींबू का फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच नींबू का रस , एक चमच्च शहद और एक चमच्च दूध को कटोरी में मिला कर मिश्रण बना लें /इस मिश्रण को चेहरे पर आधा घण्टा लगा रहने दें और बाद में साफ ताजे पानी से धो डलें / यह त्वचा की रंगत निखारने का प्रकृतिक तरीका है /दूध में बिद्यमान प्रकृतिक वसा और खनिज त्वचा को टोन करते हैं और मैग्निसियम , कैल्शियम आदि त्वचा को पौषण प्रदान करते हैं / एक चमच्च चीनी और एक चमच्च नींबू जूस को मिलाकर पेस्ट बना लें / इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा कर आहिस्ता से स्क्रब कर लें और कुछ समय बाद साफ पानी से धो डालें /इस मिश्रण को आप हफ्ते में एक बार लगा सकती है

3---खीरा ----गर्मियों में त्वचा के लिए बहुत सारे घेरलू नुस्खों में खीरा सबसे जरूरी सामग्री है. इसका एक शांत और ठंडा प्रभाव है./ एक अच्छा खीरे का फेस पैक या आपकी आंखों पर कट-अप स्लाइस आपको आराम देगा. यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है क्योंकि इसमें ब्लीचिंग गुण होते हैं. यह आपकी त्वचा की रंगत को भी हल्का करता है। आपको खीरे का रस, थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा सा नींबू का रस और एक

गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग टैनिंग को लेकर परेशान रहते हैं / हालाँकि कुछ लोग चेहरे पर कपड़ा बांध कर निकलते हैं लेकिन कड़कती धूप से बचने के लाख जतन करके भी इससे पूरी तरह बचना मुश्किल हो जाता है/ गर्मियों में घर से बाहर निकलने पर या गर्मियों की छुट्टिओं में समुद्र तट घूमते हैं तो आपकी त्वचा सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों के सम्पर्क में आने, प्रदूषण और गन्दगी के सम्पर्क में आने से सांवली पड़ जाती है / चेहरे पर सन टेन की बजह से चेहरे का सही रंग चला जाता है और चेहरे का आकर्षण भी खतम हो जाता है जिससे चेहरा डल दिखाई देने लगता है / इस मौसम में सन टेन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कई बार लोग बड़ी कम्पनियों के महँगे उत्पादों का उपयोग करते हैं लेकिन यह उत्पाद कई बार त्वचा के अनुकूल नहीं होते जिसकी बजह से त्वचा की अनेक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

रुई चाहिए. जूस बनाने के लिए खीरे को कद्दूकस कर लें. उसमें गुलाब जल डालें और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें. इसे एक बाउल में अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण को अपने चेहरे पर एक कॉटन बॉल से समान रूप से लगाएं। इसे 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें. इसे ठंडे पानी से धो लें./ खीरे , पके पपीते के गूदे ,दही में दो चमच्च ओट्स मिलाकर बने मिश्रण को चेहरे, गर्दन और खुले स्थानों पर लगा लीजिये और आधा घण्टा बाद ताजे ठन्डे पानी से धो डालिये / इसे आप हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं /

4 ----दो चमच्च जई के आटे में थोड़ा सा मठ्ठा मिलाकर पेस्ट बना लें / इस पेस्ट को चेहरे पर लगा कर आधा घण्टा बाद साफ पानी से धो डालें /

5 --- पके केले को मैश करके इसमें एक चमच्च शहद और एक चमच्च ऑलिव आयल मिला लें / इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने के आधा घण्टा बाद ठण्डे पानी से चेहरे को धो डालें

6 ---तीन चमच्च एलो वेरा जैल , एक चमच्च हल्दी और दो चमच्च शहद को एक कटोरी में मिला कर पेस्ट बना लें / इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने के 20 मिनट बाद पानी से धो डालें / इसे आप हफ्ते में एक दिन लगा सकती हैं /

एलो वेरा जेल की कुछ बूंदें रोजाना चेहरे पर लगाने से त्वचा की रंगत निखरती है और स्किन टेन की समस्या से निजात मिलती है /

7 -------बेसन का आटा और दही को बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें चुटकी भर हल्दी डालकर पेस्ट बना लीजिये / इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के आधा घण्टा बाद ठण्डे पानी से धो डालिये

8 -----एक चमच्च शहद , एक चमच्च संतरे का जूस और अण्डे का सफेद हिस्सा अच्छी तरह फेंट कर बने मिश्रण को चेहरे पर लगा कर बीस मिनट बाद ताजे पानी से धो डालिये

9 ----एक कटोरी में एक चमच्च दही में एक चमच्च का रस मिलाएं / इस पेस्ट को त्वचा पर लगाकर दस मिनट के लिए छोड़ दें और ताजे पानी से धो डालें /

10 ----एक आलू को कद्दूकश कर लें और इसका रस निकालकर त्वचा पर लगाएं और 15 मिनट बाद ताजे पानी से धो डालें /

लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेषज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में विख्यात हैं /

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

फर्जी नियुक्ति, बिना कार्य भुगतान और संपत्ति जांच में डीआईओएस लोकायुक्त के घेरे में

कुशीनगर।

फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण देने, बिना कार्य किए लाखों रुपये के एरियर भुगतान कराने और पद के दुरुपयोग से अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) श्रवण कुमार गुप्त अब लोकायुक्त जांच के घेरे में हैं। लोकायुक्त के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इस टीम में ट्रेजरी अफसर और बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है, जो वित्तीय लेन-देन, नियुक्तियों और सेवा अभिलेखों की संयुक्त जांच करेंगे। जांच टीम के गठन के साथ ही डीआईओएस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जिन फाइलों पर अब तक बिना सवाल के हस्ताक्षर होते रहे, अब उन्हीं फाइलों के खुलने का दबाव महसूस किया जा रहा है। मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आधिकारिक जांच की जद में आ चुका है। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68-2026/06 दिनांक 8 अप्रैल 2026 के माध्यम से इस मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए थे। कुशीनगर निवासी परिवादी वीरेंद्र सिंह द्वारा 61 पृष्ठों के परिवाद और सीडी साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर लोकायुक्त ने जिला प्रशासन से जांच रिपोर्ट मांगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। शिकायत में डीआईओएस पर वेतन निर्धारण में अनियमितता, सेवा पुस्तिका में कथित हेरफेर, फर्जी नियुक्तियों को वैध दर्शाने, नियमविरुद्ध एरियर भुगतान कराने, बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में गाइडलाइन की अनदेखी करने और मानकविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जांच टीम इन सभी बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा करेगी। जानकारों के अनुसार कसानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कॉलेज के सहायक अध्यापक वीरेंद्र पांडेय और श्याम नारायण पांडेय से जुड़ा मामला जांच का प्रमुख केंद्र हो सकता है। आरोप है कि दोनों शिक्षकों को दो वर्ष तक बिना वास्तविक कार्य निष्पादन के लाखों रुपये एरियर के रूप में भुगतान किया गया।

ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब सेवा का वास्तविक निर्वहन नहीं हुआ, तो भुगतान किस आधार पर और किस नियम के तहत स्वीकृत किया गया। इस पूरे प्रकरण में किस स्तर पर फाइलें चलीं, किसने अनुमोदन दिया और किसकी संस्तुति पर भुगतान हुआ, यह जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसी तरह सखवनिया स्थित महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के लिपिक अविनाश गुप्ता की नियुक्ति भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने मृतक आश्रित कोटे के तहत नियमों को दरकिनार कर नियुक्ति प्राप्त की, जबकि उनके पिता की मृत्यु के समय उनकी माता स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवा में थीं। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल एक नियुक्ति का मामला नहीं होगा, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। शिकायत में डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त पर पद के दुरुपयोग से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। यदि जांच इस बिंदु तक गहराई से पहुंचती है, तो मामला विभागीय कार्रवाई से आगे बढ़कर व्यापक कानूनी कार्रवाई का रूप ले सकता है। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में गठित जांच टीम अब पूरे प्रकरण की परतें खोलेगी। ट्रेजरी अफसर वित्तीय भुगतान और लेखा अभिलेखों की जांच करेंगे, जबकि बीएसए नियुक्तियों, सेवा पुस्तिका और शैक्षणिक अभिलेखों का परीक्षण करेंगे। लोकायुक्त ने जांच के लिए समय-सीमा भी तय की है, जिससे इस बार जांच को लंबित रखना आसान नहीं होगा। जांच टीम के गठन के बाद डीआईओएस कार्यालय में भले औपचारिक शांति दिखाई दे रही हो, लेकिन भीतर बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच टीम आरोपों की तह तक पहुंचती है या मामला एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाता है।

आम तोड़ने की बात को लेकर दंपति की क्रूरता, नाबालिग को बांधकर पीटा वीडियो वायरल

बच्चे के साथ क्रूरता करने वाले आरोपी दंपति गिरफ्तार, बच्चे का बांधा गया हाथ और पैर

महराजगंज।

पुलिस आरोपी दंपति के खिलाफ कार्रवाई कर किया चालान

जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां आम तोड़ने के मामूली विवाद ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। चौक थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दंपति ने नाबालिग बच्चे को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्चा रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह गांव के पास स्थित एक बागीचे के पास पहुंचा, जहां आम तोड़ने की बात को लेकर दंपति रामनाथ और उसकी पत्नी सरिता ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने बच्चे के हाथ-पैर बांध दिए और फिर उसे जमकर पीटा। बच्चे की चीख-पुकार के बावजूद दंपति का दिल नहीं पसीजा। घटना का वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।

पीड़ित बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में अस्वीकार्य हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। इस घटना ने इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लेना समाज के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। चौक थाना प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामले में पीड़ित बच्चे की पिता के तहरीर पर आरोपी दंपति रमानाथ और सरिता के खिलाफ संबंधित धाराओं ने मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। समाज में ऐसे कृत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 जून तक पूरी होंगी 12 नई परियोजनाएं; लापरवाही पर मिली कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

देवरिया।

जनपद में संभावित बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन के गांधी सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट लहजे में अधिकारियों को हिदायत दी कि बाढ़ निरोधी कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि तटबंधों की सतत निगरानी के साथ-साथ रेनकट और शाही ह्वेल जैसे संवेदनशील बिंदुओं को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता (बाढ़) को बोल्डर, जियोबैग और अन्य आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि नावों, नाविकों और गोताखोरों का चिन्हांकन कर उन्हें मुस्तैद रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका पिछला भुगतान लंबित न रहे। डीएम ने उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के तटबंधों का स्वयं निरीक्षण करने और राहत शिविरों के लिए स्थानों का चयन समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। बाढ़ नियंत्रण कक्षों को अभी से सक्रिय कर कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य और स्वच्छता के मोर्चे पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को खराब हैंडपंपों के रिबोर और दूषित जल वाले उथले हैंडपंपों पर लाल निशान लगाने का आदेश दिया ताकि लोग उसका पानी पीने के लिए प्रयोग न करें। पशुपालन विभाग और नगर निकायों को पशुओं के चारे व साइलेज के लिए टेंडर प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने को कहा गया। वहीं, विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लटके और ढीले तारों को तुरंत ठीक करें। स्वास्थ्य विभाग को संभावित बाढ़ वाले इलाकों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डेटा तैयार रखने के साथ ही एंटी स्नेक वेनम और लाइफ सेविंग ड्रग्स का स्टॉक रखने के निर्देश मिले हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने तटबंधों की सुरक्षा और बाढ़ के दौरान पुलिस बल की तैनाती की रूपरेखा साझा की। अधिशासी अभियंता बाढ़ राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि जनपद के 241 किलोमीटर लंबे 40 तटबंधों की सुरक्षा के लिए 12 नई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप से जुड़े तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बिना मान्यता उच्च कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई, तत्काल रोक के निर्देश

कुशीनगर। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मंडल गोरखपुर ने जनपद कुशीनगर के सुकरौली और मोतीचक विकासखंड के कई मान्यता प्राप्त विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई स्कूल निर्धारित मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन करते पाए गए। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर संबंधित विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से अमान्य कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में सीएलएस इंटरनेशनल स्कूल, तुर्कडीहा को कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्राप्त होने के बावजूद वहां कक्षा 6, 7, 8 और 9 का संचालन किया जाता मिला। इसी प्रकार जेएन इंटरनेशनल स्कूल, टीकर को कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वहां कक्षा 9 भी संचालित पाई गई। जेएसआई इंटरनेशनल स्कूल को कक्षा 8 तक की मान्यता मिली है, जबकि निरीक्षण में वहां कक्षा 9 और 10 का संचालन होता मिला।

जीएस वर्ल्ड स्कूल, अहिरौली को कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वहां उच्च कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस विद्यालय की एक नई शाखा भी संचालित मिली, जहां बिना किसी मान्यता के कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई कराई जा रही थी। निरीक्षण में इन सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे तत्काल प्रभाव से अमान्य कक्षाओं का संचालन बंद करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मान्यता के विपरीत कक्षाओं का संचालन शिक्षा नियमावली का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्षेत्र के प्रकृति इंटरनेशनल स्कूल का भी निरीक्षण किया गया। यह विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त मिला और सभी निर्धारित मानकों का पालन करता पाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षक बीएड और टीईटी अर्हता प्राप्त पाए गए। निरीक्षण में विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की आर्थिकी को भी मिलेगी रफ्तार

गोरखपुर।

पूर्वांचल और राज्य पश्चिमी हिस्से की कनेक्टिविटी होगी मजबूत, सप्लाई चेन में आएगी तेजी

गोरखपुर सहित पूर्वी यूपी के कृषि और औद्योगिक उत्पाद कम समय में भेजे जाएंगे एनसीआर और पश्चिमी यूपी के जिलों में कनेक्टिविटी की मजबूत होती श्रृंखला का खासा फायदा होगा उद्योग जगत को - एसके अग्रवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बुधवार को जन समर्पित हुए गंगा एक्सप्रेसवे के जरिये न केवल पूर्वांचल और राज्य पश्चिमी हिस्से की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी बल्कि इससे पूर्वांचल की आर्थिकी को भी रफ्तार मिलेगा। हाल के कुछ सालों में इंडस्ट्री के हब के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर में तैयार उत्पादों को, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब और आसानी से पश्चिमी यूपी व एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) भेजना सुगम हो जाएगा। कनेक्टिविटी की नई श्रृंखला का सबसे फायदा यहां के कृषि और औद्योगिक जगत को मिलेगा। कृषि और औद्योगिक उत्पादों की सप्लाई चेन अब और आसानी तथा तेजी से काम करने लगेगी। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के लिए पहले से दो एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इससे कनेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात दे रखी है। इसकी कनेक्टिविटी का पूरा फायदा आमजन के साथ उद्योग-व्यापार जगत को मिल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से भी उद्योग-व्यापार के क्षेत्र को खासा लाभ मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर रायबरेली या वाया लखनऊ, गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयार माल काफी कम समय में एनसीआर और पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों में भेजा जा सकेगा। इसी तरफ एनसीआर या इससे होते हुए अन्य राज्यों से यहां खपत होने वाले माल को मंगाने में आसानी हो जाएगी। श्री अग्रवाल का अनुमान है कि माल भेजने और मंगाने में 50 प्रतिशत तक समय की बचत हो जाएगी।

हाल के सालों में गोरखपुर में बने रेडीमेड गारमेंट्स की सप्लाई नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिम के अन्य जिलों में हो रही है। कृषि उत्पादों और टेक्सटाइल की सप्लाई का काम यहां पहले से होता रहा है। गोरखपुर में तीव्र औद्योगिक विकास के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की भी आपूर्ति एनसीआर और अन्य जिलों तक हो रही है। यह सप्लाई चेन गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से जुड़ेगी तो यहां की आर्थिकी को नया विस्तार मिल जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज से एक लिंक रोड प्रस्तावित है जो इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (गाजीपुर-लखनऊ) में सीधे जोड़ेगी। इससे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलावा अन्य जिलों तक के लिए भी यात्रा सुगम और कम समय में हो जाएगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास एक बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। इससे पूर्वांचल के लोगों का नोएडा या दिल्ली पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, भविष्य में प्रस्तावित शामली-गोरखपुर एक्सप्रेस वे (जो गंगा एक्सप्रेसवे से भी बड़ा होगा) के साथ मिलकर, यह पूरे पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम यूपी को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉरिडोर बन जाएगा।

केजरीवाल-सिसोदिया के बाद दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी, हाईकोर्ट में पेशी से इनकार

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद एक और आप नेता ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने चिट्ठी में लिखा कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं। इस केस में मैं पेश होने में असमर्थ हूं। मेरी तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं होगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी अदालत में मुकदमा आगे नहीं चलाने का फैसला बताया था। वहीं, सोमवार को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी इसी जज की अदालत में व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से पेश नहीं होने का एलान किया था। वहीं, सीबीआई की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल ने फैसला किया कि वह आगे इस मामले में न तो खुद पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील जिरह करेंगे। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को चार पत्रों का पत्र लिखकर यह जानकारी दी। पत्र में उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह निर्णय ले रहा हूं। मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हो सकता है कि इससे मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वे न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने लिखा अपने पत्र में अदालत में बहस के दौरान दी गई दलील दोहराते हुए कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि यह फैसला केवल इसी मामले तक सीमित है। उन्होंने न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के वकालत करने के कारण हाईकोर्ट से स्थानांतरण की मांग की थी। केजरीवाल ने लिखा कि न्यायमूर्ति शर्मा की टिप्पणियों से उनकी अर्जी को न्यायिक और संस्थागत अपमान के रूप में लिया गया,

यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे का हुआ उद्घाटन

हरिद्वार से भी जुड़ेगा; पीएम नरेन्द्र मोदी बोले- बंगाल जैसी बंपर वोटिंग दशकों में नहीं देखी

हरदोई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम ने सपा और कांग्रेस पर कहा- सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में चल रहीं दूसरे चरण की वोटिंग का जिक्र किया। कहा- जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। ऐसी वोटिंग दशकों में नहीं देखी। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेस-वे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेस-वे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। अब तक 11-12 घंटे लगते थे।

एक्सप्रेस-वे करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे की औसत लागत करीब 62 करोड़ 87 लाख रुपए है। मोदी ने ही 18 दिसंबर, 2021 को शाहजहांपुर में एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया

था। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे था, जिसकी लंबाई 340 किमी है। "मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है। हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी होता है। यह सिर्फ हाई-स्पीड सड़क नहीं है, बल्कि नए सपनों का गेटवे है। "पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगलराज को यूपी की पहचान बना दिया। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थीं।

आज यूपी की कानून व्यवस्था का देशभर में उदाहरण दिया जाता है। संसाधनों का बंदरबांट करने वाले जिन सपाइयों के हाथ से सत्ता गई, उन्हें यूपी की यह प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वे यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। "बंगाल में पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। "एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता, लेकिन सपा ने इसके खिलाफ वोट किया। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे।

भाजपा चुनाव में धांधली की कोशिश कर रही, केंद्रीय बल उसके इशारे पर काम कर रहे - ममता बनर्जी

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा पर राय विधानसभा चुनाव में धांधली करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय बल तथा चुनाव पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह तृणमूल के खिलाफ जनता के गुस्से को भांपकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ममता ने अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में अधिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक मानकों से गंभीर समझौता किया गया है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र ममता का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जहां उनकी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से प्रतिष्ठा की लड़ाई है।

मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा, हाथों में बंदूक थामे ट्रंप ने ईरान को हड़काया, बेहतर है समझ जाओ

नई दिल्ली। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत अचानक रद्द होने के कारण युद्धविराम वार्ता अभी भी अटकी हुई है। इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी देते हुए अपने नो मोर मिस्टर नाइस गाई (अब कोई शराफत नहीं) वाले सख्त रुख को दोहराया है। इस बार उन्होंने ईरान पर तीखा प्रहार किया है और उस पर परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए उन्होंने कहा, ईरान चीजें तीक से नहीं संभाल पा रहा है। उन्हें नहीं पता कि गैर-परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कैसे किए जाते हैं। उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे जल्द ही समझदारी से काम लें। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में भी ट्रंप ने ईरान को ऐसी ही चेतावनी दी थी। दरअसल, अमेरिका द्वारा अपने प्रतिबंध

नहीं हटाने के फैसले के जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर फिर से नाकेबंदी लगा दी थी, जिसके बाद ट्रंप का यह बयान आया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर ईरान बहुत ही निष्पक्ष और तर्कसंगत समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो अब और विनम्र व्यक्ति नहीं रह जाएगा। यह संदेश इस्लामाबाद में वार्ता के दूसरे दौर से ठीक पहले आया था, जिसे बाद में ट्रंप ने रद्द कर दिया था। यह उन घटनाओं के साथ भी मेल खाता है जिनमें कथित तौर पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं, जिनमें उनके अनुसार एक फ्रांसीसी जहाज और एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज शामिल थे। ईरान पर ट्रंप की ये नवीनतम टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका तेहरान पर एक सख्त परमाणु-केंद्रित समझौते को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है, जो यूरेनियम संवर्धन पर अंकुश लगाएगा और उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा।

असम में हिमंता, तमिलनाडु में विजय ही विजय, केरल में विजयन की छुट्टी

नई दिल्ली । असम विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत के संकेत मिल रहे हैं। सर्वे एजेंसी Akis My India के अनुमान के मुताबिक राज्य में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है।

अगर यह अनुमान नतीजों में बदलता है, तो बीजेपी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक लगा सकती है। इससे राज्य में पार्टी की पकड़ और मजबूत होने के संकेत मिलते हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और अन्य दलों का प्रदर्शन कमजोर दिखाई दे रहा है, जिससे एनडीए की राह आसान नजर आ रही है। खासकर AIUDF को इस बार कोई खास बढ़त मिलती नहीं दिख रही।

केरल के एक्जिट पोल में कांग्रेस के लिए खुशी

मैटराइज ने केरल के एक्जिट पोल में कांग्रेस सरकार का अनुमान व्यक्त किया है। कुल 140 सीटों में लेफ्ट यानी एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है जबकि कांग्रेस के अगुवाई वाले यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं।

तमिलनाडु में फिर से डीएमके की सरकार

तमिलनाडु के लिए MATRIZE का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें डीएमके के गठबंधन को 122 से 132 सीटें और एआईएडीएमके को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अन्य

के खाते में 10 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। मैटराइज के अनुमान अगर सच होते हैं तो तो सीएम एम के स्टालिन की कुर्सी बरकरार रह सकती है।

केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी

केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के एग्जिट पोल में एक बार फिर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है. एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पुदुचेरी में एनडीए को 40 फीसदी वोट शेयर के साथ 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 30फीसदी वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं।

बंगाल विधान सभा एग्जिट पोल

बंगाल की 194 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव हुए हैं। इस तरह सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को सत्ता से विदाई तो बीजेपी पहली बार सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के चार में से तीन सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो एक सर्वे में ममता बनर्जी को बहुत दिखाई गई है। हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। 4 मई को अंतिम नतीजे आएंगे।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले- ये विकास नहीं, विनाश है

नई दिल्ली ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली की ग्रेट निकोबार में चल रही 81,000 करोड़ रुपये की सबसे महत्वाकांक्षी रणनीतिक अवसंरचना परियोजना पर निशाना साधते हुए इसे हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे जघन्य अपराधों में से एक बताया। कांग्रेस नेता, जो वर्तमान में द्वीप का दौरा कर रहे हैं, ने कहा कि केंद्र की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विकास की आड़ में विनाश के अलावा कुछ नहीं है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सरकार इसे परियोजना कहती है। मैंने जो देखा है, वह कोई परियोजना नहीं है। यह लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है। यह 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन है जिसे नष्ट होने के लिए अभिशप्त

किया गया है। यह उन समुदायों को नजरअंदाज किया गया है जिनके घर छीन लिए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगलों के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वहां के पेड़ याद से भी पुराने हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जंगल पीढ़ियों से पोषित हुए हैं और द्वीप पर रहने वाले सुंदर लोगों को उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसे 'परियोजना' कहती है। मैंने जो देखा है, वह कोई परियोजना नहीं है। लाखों पेड़ काटे जाने के लिए चिह्नित हैं। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन विनाश की कगार पर है। कई समुदायों को नजरअंदाज किया गया है और उनके घर छीन लिए गए हैं। इस विवाद की जड़ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस विशाल अवसंरचना परियोजना को दी गई मंजूरी है, जिसे कांग्रेस ने पहले अधूरे और गलत योजना पर आधारित बताया था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक माल ढुलाई और रसद केंद्र बनाने की योजना को सोनिया गांधी ने पहले भी आलोचना की थी और केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और स्वदेशी समुदायों का हवाला दिया था।

मानसा कोर्ट का आदेश- एक मई को खुद पेश हों सीएम भगवंत मान, पूर्व विधायक मानशाहिया ने दर्ज करवाया था मामला

मानसा (पंजाब) । मानसा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह नागपाल की अदालत ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मानसा के पूर्व विधायक नजर सिंह मानशाहिया द्वारा सीएम मान के खिलाफ मामला दायर किया गया था। आरोप है कि जुलाई 2019 में पार्टी छोड़ने के बाद संगरूर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके चलते मामला अदालत में पहुंचा।

जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई में मुख्यमंत्री को वीडियो माध्यम से हाजिरी लगाने की अर्जी

अदालत ने खारिज कर दी थी और उन्हें 28 अप्रैल को स्वयं उपस्थित होने को कहा गया था। हालांकि मंगलवार को भी वे आवश्यक व्यस्तता के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर भी यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

शादी से लौट रहीं दो नाबालिगों से नौ लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ (सरगुजा) । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहां दो आदिवासी लड़कियों के साथ 8 से 9 लड़कों ने अलग-अलग जगह पर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल की शाम 4 नाबालिग लड़कियां शादी समारोह से देर रात घर लौट रही थीं। इस दौरान बाइक पर सवार 8-9 लड़कों ने उनका रास्ता रोका। किसी तरह दो नाबालिगों ने बचकर भाग निकलीं। वहीं दो नाबालिगों के साथ आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार, दो बजे रात को पीड़िता घर पहुंची, लेकिन डर की वजह से घर में कुछ नहीं बताया।

अपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीकी से युक्त किया जाएगा- मुख्यमंत्री

चण्डीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत सेवा, पुलिस एवं जेल विभाग द्वारा बनाए गए शार्ट टर्म एक्शन प्लान रोडमैप की विस्तार से समीक्षा की और उन्हें इसमें और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विजन 2047 में साईबर क्राईम को पूर्ण रूप से रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। रात्रि के समय कार्य करने वाली महिलाओं को घर तक छोड़ने के कार्य के लिए योजना बनाई जाए। इसके लिए महिलाएं पोर्टल के माध्यम से पुलिस को अवगत करवाएंगी। क्राईम पर अंकुश लगाने और अपराध की दर कम लाने के लिए बूथ स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉयल 112 सुविधा को पुख्ता किया जाएगा और नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्राईम सेल में बैंक कर्मी बैठे, जब भी उनके पास अपराध की कॉल

आती है तो संबंधित बैंक के खाता को तुरंत बंद कर दिया जाए जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा है। । बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इसमें जागरूकता अभियान के साथ काउंसलर भी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीकी से युक्त होना चाहिए। पुलिस को जनता का मित्र बनकर कार्य करना है, इसके लिए पुलिस कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हर क्षेत्र में निपुण होकर दक्षता से कार्य को निपटा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद में नई जेल का निर्माण करवाया जा रहा है जिसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद पंचकूला में भी जेल परिसर बनाया जाएगा। चरखी दादरी में भी नई जेल का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपराधि बाहर निकलने के बाद आसानी से अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें।

गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थय पर किया जाएगा बेहतर कार्य

पुलिस कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण

जेलों में दिया जाएगा वोकेशनल प्रशिक्षण

सेवा, पुलिस एवं जेल विभाग के शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने सेवा विभाग के रोडमैप की समीक्षा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय सुलभ करवाया जाएगा। इसके लिए सोशल प्रफोरमेंस से जोड़कर विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थय, पेयजल आदि पर बेहतर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज एवं ग्राम बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य किया जाएगा। नशे की प्रवृति से सचेत एवं बचाने के लिए मिशन मोड़ पर अभियान चलाकर ग्रास रूट पर कार्य किया जाए। युवाओं को स्वरोजगार के लिए तकनीकी एवं उद्यमिता युक्त शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा काबिल बनकर आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा तथा गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसबी /बीबी के लिए फरीदाबाद एवं रोहतक में 6 नए होस्टल बनाए जाएंगे तथा मिनियर सिटीजन के लिए सिटीजन क्लबों का निर्माण करवाया जाएगा। इस प्रकार सामाजिक कांप्लेक्ट पर व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। सामाजिक तस्की का पैमाना बेहतर होगा तो समान व राष्ट्र का विकास होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, जी अनुपमा, अनुराग अग्रवाल, डीजीपी अजय सिंघल, आलोक मित्तल, प्रधान सचिव विजय दहिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो डंपर से भिड़ी, एक ही पल में बुझ गई 6 जिंदगियां

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर मां चंद्रिका देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो भीषण हादसे का शिकार हो गई, हादसा इतना भीषण था कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों अस्पताल पहुंचाया जहां पर 6 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वाले में पांच महिलाएं शामिल है।

6 की मौत, मृतकों में 5 महिलाएं शामिल

मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिले के बिहार थाना क्षेत्र के कीरतपुर-सुमेरपुर गांव के पास हुई, जहां बोलेरो और एक डंपर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में 5 महिलाओं समेत छह लोगों की जान गई है। तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल ले जाते समय और

इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मृत महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। शुरुआती आशंका तेज रफ्तार और लापरवाही को लेकर जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। डंपर चालक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खूनी बुधवार को घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए।